



दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कोविड के पुनः सक्रिय होने पर रिपोर्ट मांगी

न्यायालय ने यह जानकारी भी मांगी कि क्या सेंपल कलैक्शन, सेंपल कलैक्शन सेंटर तथा सेंपल ट्रांसपोर्टेशन के स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर दिये गये हैं

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-
नई दिल्ली, 2 जून। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि “अगली कोविड-19 महामरी अभी खत्म नहीं है”, केन्द्र सरकार से सेंपल कलैक्शन संग्रह, सेंपल कलैक्शन सेंटर तथा सेंपल के परिवहन की नीति पर क्या निर्णय लिया गया है, इस पर स्थिति-रिपोर्ट मांगी है।

28 मई को दिए गए अदेश में न्यायमूर्ति अनेश दालन ने कहा कि यह मामला अवश्यक हो गया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर खबरें आ रही हैं कि “कोविड-19” सक्रिय हो गया है।

कोटि ने कहा, “कलमन स्थिति को देखते हुए अपेक्षित है कि विवादी तत्काल उपर्योग का एक स्पष्ट खाका तैयार कर, ताकि स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) तापू की जा सके और बैठक में लिया गया निर्णय अपने उचित निकर्ष तक पहुँचे।”

यह मामला डॉ. रोहित जैन द्वारा

- न्यायालय ने कहा, 30 मई, 2023 को अतिरिक्त निर्देशक जनरल ऑफ हैल्थ सर्विसेज, की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोविड के पुनः प्रसार को रोकने के लिए कई निर्णय लिये गये थे, जिनमें कोविड के संदर्भ में चार उपसमितियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया था।
- न्यायालय ने 30 मई, 2023 को आयोजित इस बैठक में कोविड के संबंध में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।

दाव एक अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें उल्लेख 27 जनवरी, 2023 को देखते हुए अपेक्षित है कि विवादी तत्काल उपर्योग का एक स्पष्ट खाका तैयार कर, कोटि ने करने के अपराध लागत है।

खड़ीपैट ने इस मुद्दे पर जैन को याचिका को निस्तारित करते हुए, केन्द्र सरकार को इसे एक “रैप्रैट्रैनेशन” के रूप में मानकर 12 सप्ताह के भीतर कारण सहित निर्णय लेने के निर्देश दिया

भी आमंत्रित किया गया था।

इस बैठक में पैथॉलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, हीमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञों की चार उप-समितियों का गठन करने का निर्णय उपर्याक्षर के बैठक सरकार के केंद्र सरकार के केंद्र विवाद खड़ा कर दिया गया है और संसोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

बैठक ने सोमवार को यहां जारी एक नोटिस भेजा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नीट-पीजी 2025 की प्रोस्ला एक पाली में आयोजित की जाएगी।

आसान में यह भी उल्लेख है कि दिशा-निर्देशों में स्टोरज स्टैण्डर्डर्स (रैंडर) में की शामिल किया जाना था। बैठक में अन्य कारबिंग्यों पर भी सहमति बनी थी, जिसे अदालत ने नोट किया।

न्यायमूर्ति दालन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने यह नहीं बताया कि 30 मई, 2023 की बैठक का क्या परिणाम निकला और क्या निर्णय लिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि पहली दृष्टि में यह अवमानना याचिका बनी नहीं रह गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

15 जून को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित

नयी दिल्ली, 02 जून। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2025 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और संसोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी।

बैठक ने सोमवार को यहां जारी एक नोटिस भेजा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नीट-पीजी 2025 की प्रोस्ला एक पाली में आयोजित की जाएगी।

- परीक्षा बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार एक पाली में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है, नई तिथि जल्दी ही घोषित की जाएगी।

नोटिस के अनुसार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक पाली में परीक्षा करने के लिए आयुर्व्यक्ति विवादों के निर्णय दालन की जारी है और परीक्षा की संसोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। बोर्ड ने कहा है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2025 को स्थगित कर दिया गया।

सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके भारी अपेक्षाने की स्थगित करने के लिए एयर काप्ट डील करने की अत्यावश्यकता को नहीं समझती है, ना ही टैक्सोलॉजी एंड स्पेशलिस्ट के अनुरूप एक उच्चारण के लिए स्पेशलिस्टों का कहना है कि सरकार निर्णय दालन की जारी है और परीक्षा की तैयारी की जारी है। विवेजों का कहना है कि सरकार निर्णय दालन की जारी है और परीक्षा की तैयारी की जारी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीफ ऑफ डिफैस स्टाफ की स्पष्ट स्वीकृति ने कई सवाल उठाये, “सरकार की तैयारी” के बारे में

सीडीएस अनिल चौहान ने वायु सेना की तैयारी और मार्डनाइजेशन के बारे में सरकार के दावों को खोखला साबित करने का प्रयास बताया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 2 जून। चीफ ऑफ डिफैस स्टाफ स्पष्ट चौहान ने भारत के प्रारंभ-विवादों में आयोजित बैठक में आयोजित बैठक में कोविड के पुनः प्रसार को रोकने के लिए कई निर्णय लिये गये थे, जिनमें कोविड के संदर्भ में चार उपसमितियां गठित करने का भी निर्णय लिया गया था।

बैठक ने सोमवार को यहां जारी एक नोटिस भेजा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नीट-पीजी 2025 की प्रोस्ला एक पाली में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा के अनुसार न्यायालय

- एक अन्य रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने कहा कि कारगिल की लाइफ के दौरान भी वायु सेना में 12 स्वरूप्रान की कमी थी तथा डिफैस रिव्यू कमेटी ने भी वायु सेना की इस कमी पर काफी फोकस किया था।

सभी सरकारों ने वायु सेना की बढ़ने से रोकने के लिए काफी प्रयास किये, पर, सीडीएस के अनुसार हासिल करने में इस कमी की भरपाई के लिए एयर काप्ट डील करने के लिए आयोजित विवादों के अनुरूप एक उच्चारण की जारी है।

पूर्व जनरल मोहन भंडारी ने इस “स्टो डाउन” को स्वीकार किया, पर, इस बात पर भी जो दिया गया था कि डिफैस लीडरशिप को युद्ध की तैयारी में पूरी तरह तत्पर ही नहीं बल्कि सेना के अधिकारियों को सार्वजनिक बातचीत में माहिर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, सेना के उच्च अधिकारियों को जनता से “बातचीत” करने में महारथ हासिल करना भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया है।

स्वीकृत स्तर से कम की स्कॉर्ऱन क्षमता उसने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका “कारगिल वार्ड के बाद से ही हमारे पास गंभीरता से सेनान नहीं किया गया।”

रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने कहा कि भारी अपेक्षाने की स्थगित करने के लिए एयर काप्ट डील करने की स्थगित करने की जारी है।

उसने एक अंतिम पृष्ठ पर

‘इलाज के लिए घंटों इंतजार कराया, अन्ततोगत्वा दुष्कर्म पीड़ित बालिका ने दम तोड़ा’

बिहार में समूचे विपक्ष ने यह आरोप लगाते हुए बालिका की मृत्यु के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेवार ठहराया

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 2 जून। बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले में नी वर्ष की एक विवादी दालिका के प्रक्रियाकाल सेमेंट के लिए आयुर्व्यक्ति विवादों के निर्णय दालन की जारी है।

रिटायर्ड विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने यह भी कहा कि इनमें से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से हो गए हैं।

इनमें से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से हो गए हैं।

इनमें से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से हो गए हैं।

इनमें से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से दो द्रुमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन से हो गए हैं।</

